



# बिहार गजट

## असाधारण अंक

### बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित

---

17 ज्येष्ठ 1940 (श10)  
(सं0 पटना 525) पटना, वृहस्पतिवार 7 जून 2018

---

सं0 08/आरोप-01-92/2017 सा0प्र0-1460

सामान्य प्रशासन विभाग

संकल्प

30 जनवरी 2018

श्री सीताराम यादव (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 694/08 (460/11), तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, फुलपरास, मधुबनी सम्प्रति सेवानिवृत्त के विरुद्ध ग्रामीण विकास विभाग के पत्रांक 5282 दिनांक 15.06.2007 द्वारा प्रपत्र 'क' में आरोप पत्र प्राप्त हुआ था, जिसमें इंदिरा आवास सामान्य एवं विशेष में अनियमितता एवं भ्रष्टाचार का आरोप प्रतिवेदित था। प्रतिवेदित आरोप के विरुद्ध श्री यादव से विभागीय पत्रांक 9684 दिनांक 25.09.2007 द्वारा स्पष्टीकरण की मांग की गई तथा प्राप्त स्पष्टीकरण पर ग्रामीण विकास विभाग का मंतव्य प्राप्त किया गया। ग्रामीण विकास विभाग द्वारा अपने मंतव्य में श्री यादव के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही चलाने की अनुशंसा की गई। ग्रामीण विकास विभाग के उक्त अनुशंसा के आलोक में श्री यादव के विरुद्ध विभागीय संकल्प संख्या 5541 दिनांक 17.05.2011 द्वारा विभागीय कार्यवाही संचालित की गई।

विभागीय कार्यवाही के फलस्वरूप प्राप्त जाँच प्रतिवेदन में श्री यादव के विरुद्ध प्रतिवेदित कुल आठ आरोपों में से दो आरोप प्रमाणित एवं दो आरोप अंशतः प्रमाणित तथा चार आरोप अप्रमाणित पाया गया। प्राप्त जाँच प्रतिवेदन पर श्री यादव से लिखित अभ्यावेदन की मांग की गई। श्री यादव द्वारा अपने अभ्यावेदन में कोई नया तथ्य नहीं दिया गया। केवल पूर्व की बातों को ही दुहराया गया।

श्री यादव के विरुद्ध प्रतिवेदित आरोपों एवं प्राप्त स्पष्टीकरण तथा प्राप्त जाँच प्रतिवेदन की पूर्ण समीक्षा अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा की गई एवं निम्नलिखित दण्ड देने का निर्णय लिया गया :-

(i) वर्तमान कोटि से निम्नतर कोटि एवं वेतनमान में पदावनति। इसके फलस्वरूप इनकी वरीयता पदावनत कोटि में वर्तमान पदाधिकारियों में सबसे उपर रहेगी।

(ii) प्रोन्नति पर रोक।

उक्त प्रस्तावित दण्ड पर बिहार लोक सेवा आयोग से विभागीय पत्रांक 2197 दिनांक 09.02.2012 द्वारा परामर्श की मांग की गयी। बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा अपने पत्रांक 570 दिनांक 11.06.2012 द्वारा प्रस्तावित दण्ड को आनुपातिक नहीं मानते हुए दण्ड प्रस्ताव से असहमति व्यक्त की गई है। आयोग के परामर्श पर अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा विचारोपरांत यह पाया गया कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा प्रस्तावित दण्ड पर असहमति के संबंध में कोई विशिष्ट कारणों का उल्लेख नहीं किया गया है।

अतः आयोग के अभिमत से असहमत होते हुए श्री सीताराम यादव (बि0प्र0से0), कोटि क्रमांक 694/08, तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी, फुलपरास, मधुबनी को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 (समय-समय पर यथा संशोधित) के नियम 14(viii) एवं 14 (ii) के तहत विभागीय संकल्प संख्या-10956 दिनांक 06.08.2012 द्वारा निम्नलिखित शास्ति संसूचित की गयी:-

(i) वर्तमान कोटि से निम्नतर कोटि एवं वेतनमान में पदावनति। इसके फलस्वरूप इनकी वरीयता पदावनत कोटि में वर्तमान पदाधिकारियों में सबसे उपर रहेगी।

(ii) प्रोन्नति पर रोक।

उक्त दण्डादेश के विरुद्ध श्री यादव द्वारा समर्पित पुनर्विलोकन अभ्यावेदन को विभागीय संकल्प ज्ञापांक 16039 दिनांक 27.11.2012 द्वारा अस्वीकृत कर दिया गया।

उक्त संसूचित दण्डादेश संकल्प 10956 दिनांक 06.08.2012 एवं पुनर्विलोकन अभ्यावेदन की अस्वीकृति संबंधी संकल्प ज्ञापांक 16039 दिनांक 27.11.2012 के विरुद्ध श्री यादव द्वारा माननीय उच्च न्यायालय, पटना में याचिका सी0डब्ल्यू0जे0सी0 संख्या 21831/2012 दायर किया गया। जिसमें माननीय उच्च न्यायालय द्वारा दिनांक 01.12.2017 को न्यायादेश पारित किया गया है, जिसका मुख्य कार्यकारी अंश निम्नवत् है:-

“..... The procedure which has been followed in the present case is completely not in terms of aforesaid C.C.A. Rule. Procedure prescribed in the Rule is not mere a formality but it has been framed with the certain purpose to grant proper opportunity to the delinquent to defend himself and the inquiry officer analyzing the evidence produced before him will arrive to a finding on the basis of documentary evidence as well as oral evidence and the oral evidence has to be proved through witness. The manner in which the inquiry has been conducted it is foreign to the known procedure of law and not compatible with the procedure prescribed under the C.C.A. Rules.

In such view of the matter, the order dated 06-08-2012 (Annexure-18) as well as the order of review dated 27-11-2012 (Annexure-23) are quashed. The matter is remanded back to the respondent authorities, if they so like, may conduct fresh inquiry in C.C.A. Rules.

Learned counsel for the petitioner submits that during the pendency of the writ application the petitioner has already superannuated on 30-04-2013. In such view of the matter, the proceeding can only be initiated under the Bihar pension Rules, but while conducting the inquiry, the Inquiry Officer will have to follow proper procedure prescribed in the C.C.A. Rules.

With the aforesaid observations and directions, this writ application is allowed.”

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त न्यायादेश के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त अनुशासनिक प्राधिकार द्वारा न्याय निर्णय का अनुपालन करते हुए निम्न निर्णय लिया जाता है:-

1. श्री यादव के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालन हेतु पूर्व निर्गत संकल्प ज्ञापांक 5541 दिनांक 17.05.2011 तथा संसूचित शास्ति से संबंधित संकल्प ज्ञापांक 10956 दिनांक 06.08.2012 एवं पुनर्विलोकन अभ्यावेदन अस्वीकृति से संबंधित संकल्प ज्ञापांक 16039 दिनांक 27.11.2012 को निरस्त किया जाता है।

2. माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित उक्त न्यायादेश दिनांक 01.12.2017 की कंडिका-9 के अनुरूप श्री यादव के विरुद्ध बिहार पेंशन नियमावली के नियम-43 'बी' के तहत नये सिरे से विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु विभागीय जाँच आयुक्त, बिहार, पटना को संचालन पदाधिकारी तथा जिला पदाधिकारी, मधुबनी द्वारा नामित कोई वरीय पदाधिकारी को प्रस्तुतीकरण पदाधिकारी नियुक्त किया जाता है।

3. उक्त प्रस्ताव में माननीय मुख्यमंत्री का अनुमोदन प्राप्त है।

श्री यादव से यह अपेक्षा की जाती है कि वे अपने बचाव के संबंध में अपना पक्ष रखने हेतु जैसा संचालन पदाधिकारी अनुमति दे, उनके समक्ष उपस्थित होंगे।

आदेश:-आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प को बिहार राजपत्र के अगले असाधारण अंक में प्रकाशित किया जाय तथा इसकी प्रतियाँ सभी संबंधित को भेज दी जाय।

बिहार-राज्यपाल के आदेश से,

भीम प्रसाद,

सरकार के संयुक्त सचिव।

अधीक्षक, सचिवालय मुद्रणालय,

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

बिहार गजट (असाधारण) 525-571+10-डी0टी0पी0।

Website: <http://egazette.bih.nic.in>